

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
नागरिक अपील न्यायपालिका

2020 की सिविल अपील No.603
(2019 के एस. एल. पी. (सी) No.26267 से बाहर निकलते हुए)

भारत का संघ

अपीलार्थी (ओं)

बनाम

स्व-वित्तपोषित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का संगठन
पंजाब और ओआरएस।

उत्तरदाता (ओं)

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 589
(2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 25464 से उत्पन्न)

2019 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1395

2019 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1461

2020 की सिविल अपील No.602
(2019 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 29172 से उत्पन्न)

2020 की सिविल अपील संख्या 605
(2019 के एस. एल. पी. (सी) No.29792 से बाहर निकलते हुए)

2020 की सिविल अपील No.606
2020 का (@एस. एल. पी. (सी) No.2493 @डायरी संख्या (ओं)।

2020 की सिविल अपील संख्या 607
(2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 29 से बाहर निकलते हुए)

2020 की सिविल अपील No.608
2020 का (@एस. एल. पी. (सी) No.2494 @डायरी संख्या (ओं). 2020 की 356

2020 की सिविल अपील संख्या 604
(2019 के एस. एल. पी. (सी) No.26724 से बाहर निकलते हुए)

2020 की सिविल अपील संख्या 609
(2020 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 518 से उत्पन्न)

2020 की सिविल अपील संख्या 610
(2020 के एस. एल. पी. (सी) No.1155 से उभरना)

जे यू डी जी एम ई एन टी

एल. नागेश्वर राव, जे.

1. केंद्र द्वारा जारी अधिसूचनाओं की वैधता
भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद के रूप में संदर्भित, 'केंद्रीय परिषद') और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद
अखिल भारतीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश निर्धारित करना
स्नातक में प्रवेश के लिए परीक्षा (संक्षेप में, 'एन. ई. टी.')

पाठ्यक्रम (बीएएमएस, बी. यू. एम. एस., बीएसएमएस और बीएचएमएस) और न्यूनतम
उक्त परीक्षा में योग्यता अंक, में उत्पन्न होते हैं

ऊपर अपील और रिट याचिकाएँ। ये अधिसूचनाएँ
आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करें
शैक्षणिक वर्ष से 2019-2020। इसी तरह, की वैधता
आयुष स्नातकोत्तर की शुरुआत करने वाली अधिसूचना
स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा (एआईए-पीजीईटी)
पाठ्यक्रम (एम. डी.-आयुर्वेद) और न्यूनतम निर्धारित करना
उपरोक्त अपीलों में योग्यता अंक भी उत्पन्न होते हैं।

2. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी (संक्षेप में, 'आयुष'), सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया और आयुष में छात्रों को प्रवेश देने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम 2018-2019 केवल एन. ई. टी. की योग्यता सूची के आधार पर, द्वारा आयोजित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मौजूदा नियमों और आरक्षण नीतियों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों का। न्यूनतम अंडर में प्रवेश की पात्रता के लिए योग्यता चिह्न

स्नातक पाठ्यक्रम 50वें प्रतिशत पर निर्धारित किए गए थे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचितों के लिए न्यूनतम अंक जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को 40 तारीख को निर्धारित किया गया था प्रतिशत। प्रतिशत इस आधार पर निर्धारित किया जाएगा अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में प्राप्त अंकों की संख्या एन. ई. टी. इसके बाद, दिनांक 07.12.2018 की अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की परिषद (भारतीय में शिक्षा के न्यूनतम मानक) चिकित्सा) संशोधन विनियम, 2018 (इसके बाद) '2018 विनियम) के रूप में संदर्भित। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (शिक्षा के न्यूनतम मानक)

भारतीय चिकित्सा में) विनियम, 1986 में संशोधन किया गया था
2018 के विनियम। 2018 का विनियमन 2 (डी)
विनियमों में प्रावधान है कि एक वर्दी होगी
सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, अर्थात्
प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एन. ई. टी.)
प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रमों और
एन. ई. टी. परीक्षा एक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा नामित। न्यूनतम
स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता चिह्न
सामान्य श्रेणी के लिए 50 वें प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है
उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों के लिए 40वां प्रतिशत और
अनुसूची जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार।
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर)
आयुर्वेदिक शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018 थे -
भारतीय चिकित्सा केंद्र में संशोधन करते हुए जारी किया गया
परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा) विनियम,
2016. अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (ए. आई. ए-पी. जी. ई. टी.)
अंडर के लिए निर्धारित परीक्षा की पंक्तियाँ
स्नातक पाठ्यक्रम, उक्त नियमों द्वारा शुरू किए गए थे
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए।

3. गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर,
पंजाब ने प्रवेश के लिए 31.07.2019 पर एक विवरण पुस्तिका जारी की
न्यूनतम निर्धारित बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रम
एन. ई. टी. में अंक और अंडर में प्रवेश के लिए मानदंड
स्नातक पाठ्यक्रम। 2019 की सिविल रिट याचिका में No.23710
आयुष महाविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा दायर, उच्च
पंजाब और हरियाणा की अदालत ने एक अंतरिम आदेश पारित किया
06.09.2019 छात्रों को अंडर में प्रवेश की अनुमति देना
स्नातक पाठ्यक्रम (बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस) बिना
छात्रों को न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त करने पर जोर देना
एन. ई. टी. में प्रतिशत। इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे
पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अन्य रिट याचिकाओं में।
आयुर्वेदिक द्वारा दायर सभी रिट याचिकाएँ और
होम्योपैथिक कॉलेजों को उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था
पंजाब और हरियाणा दिनांकित अपने फैसले द्वारा 18.12.2019।
उक्त निर्णय से व्यथित, महाविद्यालयों के साथ-साथ
छात्रों ने हमारे सामने ये विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं।
छात्रों द्वारा दायर अन्य एस. एल. पी. हैं जो मांग कर रहे हैं
स्नातक पाठ्यक्रमों (बीएएमएस, बीयूएमएस और
बी. एच. एम. एस.) शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए।
के आधार पर संस्थानों में छात्रों को प्रदान किया गया

इस पर जोर दिए बिना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश
2018 के विनियमों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड अर्थात्
एन. ई. टी. में न्यूनतम अंक प्राप्त करना। केंद्रीय परिषद
अंतरिम आदेशों से व्यथित होकर कुछ एसएलपी भी दायर किए हैं
प्रवेश की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालयों द्वारा पारित
एन. ई. टी. पात्रता पर जोर दिए बिना छात्र

स्नातक के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

4. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह बिंदु जो हमारे लिए उत्पन्न होता है
विचार यह है कि क्या छात्र प्रवेश चाहते हैं
स्नातक पाठ्यक्रमों (बी. ए. एम. एस., BUMS, BSMS और
बी. एच. एम. एस.) और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को अस्वीकार किया जा सकता है।
इस आधार पर प्रवेश कि उन्होंने एन. ई. टी. नहीं ली थी
या कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत नहीं मिला
2018 के विनियमों के अनुसार। इसे संदर्भित करना सुविधाजनक होगा।
2020 के एस. एल. पी. (सी) No.29 में तथ्यों के लिए जो दायर किए गए हैं।
पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ और
सिविल रिट याचिका में हरियाणा दिनांकित 18.12.2019

2019 (ओ एंड एम), प्रमुख मामले के रूप में।

5. उच्च न्यायालय में, इसकी ओर से तर्क दिया गया था
जिन संस्थानों ने 2018 में रिट याचिका दायर की थी
नियम भारतीय चिकित्सा केंद्र के अधिकार से परे हैं।

परिषद अधिनियम, 1970 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।
तर्क दिया गया था कि अखिल भारतीय परीक्षा की शुरुआत
एन. ई. टी. का रूप विनियमन बनाने से परे है
धारा 36 के तहत केंद्रीय परिषद का प्राधिकरण
अधिनियम. रिलायंस को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा इस पर रखा गया था
तथ्य यह है कि एन. ई. टी. परीक्षा इसके लिए शुरू की गई थी
प्रावधानों में संशोधन के बाद ही एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम
क्रमशः 1948. संदर्भ दिया गया था
धारा 10 और धारा 33 में किए गए संशोधन
अधिनियम और दोनों में धारा 10-ए की शुरुआत
उपरोक्त अधिनियम। यह तर्क दिया गया था कि बिना
के प्रावधानों में संशोधन करने का एक समान अभ्यास करना
केंद्रीय परिषद को ऐसा करने का अधिकार देने वाला अधिनियम
प्रवेश परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले नियम, केंद्रीय
परिषद ने जल्दबाजी में 2018 के नियम बनाए।
अदालत ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया
आयोजित करके संस्थानों की ओर से उठाए गए विवाद
कि दिनांकित 07.12.2018 विवादित नियम ठीक थे
केंद्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर
अधिनियम. स्नातक पाठ्यक्रमों में किए गए प्रवेश

एन. ई. टी. के बिना छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2019-2020

पात्रता को अस्थिर पाया गया क्योंकि वे थे

2018 के विनियमों के विपरीत। उच्च न्यायालय ने कहा कि

छात्र किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते क्योंकि अंतरिम

जिनके आधार पर प्रवेश दिए गए थे

छात्रों ने निर्धारित किया कि उनका प्रवेश विषय होगा

लेखन याचिकाओं के अंतिम परिणाम तक।

6. यह संस्थाओं की ओर से तर्क दिया गया था और

छात्रों का कहना है कि 2018 के विनियम अधिनियम के अधिकार से परे हैं।

केंद्रीय परिषद को ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है

अखिल भारतीय प्रवेश की शुरुआत के लिए नियम

अधिनियम की धारा 36 के तहत जाँच। यह मानते हुए कि

नियम सामान्य नियम बनाने के तहत बनाए गए थे

शक्तियाँ, संस्थाओं की ओर से समर्पण और

छात्र थे कि 2018 के नियम में नहीं हैं

धारा 36 (1) के तहत "अधिनियम के उद्देश्यों" के अनुरूपता

अधिनियम का। प्रस्तुतियों के समर्थन में, संदर्भ था

किए गए संशोधनों में किया गया

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम

1948 विनियम बनाने से पहले जिसके द्वारा अखिल भारतीय

स्नातक और पद में प्रवेश के लिए परीक्षाएँ

स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। आगे की प्रस्तुति छात्रों और संस्थानों का कहना था कि एन. ई. टी. नहीं है। आयुष के पाठ्यक्रम के रूप में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों के लिए संरचित पाठ्यक्रम एमबीबीएस के पाठ्यक्रम से पूरी तरह से अलग हैं या बीडीएस पाठ्यक्रम।

7. इसके विपरीत, सुश्री पिंगी आनंद, विद्वान अतिरिक्त केंद्रीय परिषद की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत किया कि 2018 के नियम पूरी तरह से मान्य हैं शक्ति के वैध प्रयोग में किया गया है केंद्रीय परिषद को धारा 36 के तहत प्रदान किया गया अधिनियम. सुश्री आनंद ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 22 शिक्षा के न्यूनतम मानकों से संबंधित भारतीय चिकित्सा में प्रवेश करने की शक्ति शामिल है। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा। सुश्री आनंद के अनुसार, केंद्रीय परिषद को बदनाम नहीं किया गया है अधिनियम की धारा 36 के रूप में विनियम बनाने की शक्ति परिषद को आम तौर पर लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। उन्होंने आग्रह किया कि न्यूनतम अंडर में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यता प्रतिशत स्नातक पाठ्यक्रम (बी. ए. एम. एस., बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस) हैं। न्यूनतम बनाए रखने के लिए आवश्यक

शिक्षा के मानक। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य

पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानक तय किए जाते हैं।

एक विस्तृत अध्ययन और शुद्धता के आधार पर

इस तरह का निर्णय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

8. भारतीय के प्रावधानों को संदर्भित करना प्रासंगिक है।

चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970. अधिनियम की धारा 22

केंद्रीय परिषद को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है

भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक जो

मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं

भारत में विश्वविद्यालयों, बोर्डों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा।

धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय परिषद,

केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी

आम तौर पर अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम।

धारा 36 (i), (जे) और (पी) इस प्रकार हैं:

(i) पाठ्यक्रम और अध्ययन की अवधि और व्यावहारिक

शुरू किया जाने वाला प्रशिक्षण, परीक्षा के विषय

और उसमें प्राप्त की जाने वाली प्रवीणता के मानक,

अनुदान के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सा संस्थानों में

मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता;

(ज) कर्मचारियों, उपकरणों, आवास के मानक,

भारत में शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं

दवा;

(ट) व्यावसायिक परीक्षाओं का संचालन,
परीक्षकों की योग्यताएँ और शर्तें
ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश;
(पी) कोई भी मामला जिसके लिए इस अधिनियम के प्रावधान के तहत
नियमों द्वारा किया जाए। "

9. हम इस पर किए गए तर्क से सहमत हैं
छात्रों और संस्थानों की ओर से जो परिचय देते हैं
अखिल भारतीय परीक्षा अनुभाग द्वारा कवर नहीं की जाएगी।
अधिनियम की धारा 36 (i), (जे) और (के)। हालाँकि, धारा 36 (पी) का उल्लेख है
अधिनियम के तहत किसी भी मामले के लिए जिसके लिए प्रावधान हो सकता है
विनियमों द्वारा बनाए गए। हमारी विचारशील राय में,
धारा 22 जो न्यूनतम मानकों से संबंधित है -
भारतीय चिकित्सा में शिक्षा, सभी के विषय को शामिल करती है
भारत सामान्य प्रवेश परीक्षा। हम इसमें समर्थित हैं

पशु चिकित्सा में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा यह दृष्टिकोण
भारतीय परिषद बनाम भारतीय कृषि परिषद
अनुसंधान 1. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की धारा 22
अधिनियम भारतीय परिषद की धारा 22 के अनुरूप है।
चिकित्सा अधिनियम. एक अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश
द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा परीक्षा शुरू की गई थी
1993 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और एक परीक्षा
इसके अनुसार शैक्षणिक वर्ष से आयोजित किया गया था

1995-1996. की वैधता से संबंधित विवाद

विनियमों को इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करके हल किया गया था कि

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद तैयार करने के लिए अधिकृत है।

पशु चिकित्सा के मानकों को निर्धारित करने वाले नियम

शिक्षा और ऐसी शक्ति में बनाने की शक्ति शामिल है

प्रवेश और पशु चिकित्सा अनुदान से संबंधित विनियम

योग्यताएँ। इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्राधिकरण

प्रवेश के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है

शिक्षा के मानकों को बनाए रखना। तत्काल मामला

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (ऊपर) इसलिए, हम हैं

राय है कि 2018 के विनियमों को नहीं कहा जा सकता है

अधिनियम के अधिकार में है।

10. स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि

शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए पाठ्यक्रम 15वें स्थान पर थे।

स्नातकोत्तर के लिए अक्टूबर, 2019 और 31 अक्टूबर 2019

पाठ्यक्रम। की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक

संस्थान और छात्र बड़ी संख्या में

पहले वर्ष में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी में सीटें

पाठ्यक्रम नहीं भरे गए हैं। उदाहरण के लिए, श्री पी. एस. पटवालिया,

विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 540 सीटें हैं

प्रथम वर्ष के बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध
गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय। केवल 27 सीटें हो सकती हैं
25.06.2019 पर आयोजित अखिल भारतीय परामर्श में भरा गया।
दूसरी परामर्श जो 24.07.2019 पर आयोजित की गई थी, केवल
28 उम्मीदवार पात्र पाए गए। राज्य के बाद
540 सीटों में से 320 सीटें रिक्त रहीं।
पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का आधार
और हरियाणा में बिना जोर दिए प्रवेश दिए गए

एन. ई. टी. और इस प्रक्रिया में 275 सीटें भरी गईं।

11. इसी तरह के बयान दिए गए थे

अन्य राज्यों के संस्थान और छात्र जो

एन. ई. टी. में न्यूनतम योग्यता अंकों पर जोर देना

अंडर में बड़ी संख्या में सीटें प्रदान करेंगे

शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम 2018-2019

खाली है। विद्वान वकील ने एक जोरदार याचिका दायर की थी।

छात्रों के लिए उपस्थित होना कि उन्हें अनुमति दी जा सकती है

जारी रखें क्योंकि उन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है और वे

उनके प्रवेश की स्थिति में एक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद हो जाएगा

रद्द कर दिया गया। किसी भी स्थिति में, उनके द्वारा खाली की गई सीटें

भरा नहीं जा सकता।

12. प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करना
वर्ष 2019-2020 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम थे
केंद्रीय परिषद और संघ द्वारा जोरदार बचाव किया गया
भारत का यह प्रस्तुत करके कि न्यूनतम मानक नहीं कर सकते हैं
आयुष पाठ्यक्रमों के लिए भी कम किया जाए। हम सहमत हैं। डॉक्टर
जो आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में योग्य हैं
धाराएँ भी रोगियों का इलाज करती हैं और न्यूनतम की कमी
शिक्षा के मानकों के परिणामस्वरूप आधे पके हुए डॉक्टर होंगे
पेशेवर कॉलेजों से बाहर किया जा रहा है। अनुपलब्धता
आयुष में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या
स्नातक पाठ्यक्रम कम करने का कारण नहीं हो सकते हैं।
प्रवेश के लिए केंद्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानक।
हालांकि, बड़ी संख्या में प्रवेश को देखते हुए
आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्र
पारित अंतरिम आदेशों के बल पर वर्ष 2019-2020
उच्च न्यायालयों द्वारा, हम निर्देश देते हैं कि छात्र
जारी रखने की अनुमति दी गई बशर्ते कि उन्हें प्रवेश दिया गया हो
प्रवेश की अंतिम तिथि यानी 15 अक्टूबर, 2019 से पहले।
उक्त निर्देश प्रवेश लेने वाले छात्रों पर भी लागू होता है।
31 अक्टूबर, 2019 से पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए।
एक बार का अभ्यास है जिसकी अनुमति दी गई है

विशिष्ट परिस्थितियाँ। इसलिए, यह आदेश नहीं होगा

एक मिसाल के रूप में माना जाता है।

13. दिनांकित अधिसूचना 14.12.2018 से संबंधित

होम्योपैथी पाठ्यक्रम आयुष के समान हैं।

पाठ्यक्रम। यह होम्योपैथी की ओर से तर्क दिया गया था

कॉलेज जो धारा 20 (2) में निर्धारित प्रक्रिया

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (संक्षेप में,

'1973 अधिनियम') का संशोधन से पहले पालन नहीं किया गया था

विनियमों के अनुसार किया गया। की कमी को देखते हुए

उस समय, केंद्रीय परिषद द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था

होम्योपैथी या भारत संघ द्वारा तथ्यात्मक को स्पष्ट करना

प्रक्रिया के गैर-अनुपालन से संबंधित स्थिति

विनियम बनाने के लिए 1973 के अधिनियम के तहत निर्धारित।

उसी के दृष्टिकोण से, हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं

रिट याचिका (सी) No.1461 में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

2019 का। हम इसे याचिकाकर्ताओं के लिए खुला छोड़ते हैं कि वे इन्हें उठाएं।

उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दे, यदि वे इसे उचित और उचित समझते हैं।

विभिन्न प्रस्तुतियों से निपटना आवश्यक नहीं है।

द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया

हम छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के लिए, सभी अपीलें
और रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया जाता है।

..II.
[एल. नागेश्वर राव]

..III.
नई दिल्ली,
20 फरवरी, 2020।
[दीपाक गुप्ता]